भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3191
22 मार्च, 2022 को उत्तरार्थ

उत्तर प्रदेश के जिला सरकारी बैंकों का पुनरुद्धार

3191: श्री हरीश द्विवेदी:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार और नाबार्ड ने उत्तर प्रदेश के कुछ छोटे और कमजोर जिला सहकारी बैंकों के पुनरुद्धार के लिए वर्ष 2015 में किसी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं; और
(ख) यदि हां, तो उक्त बैंकों के नाम और इस संबंध में कितनी राशि जारी की गई है ?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) एवं (ख) भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और नाबार्ड ने 16 फरवरी 2015 को उत्तर प्रदेश राज्य में 16 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के पुनरुद्धार की योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें इन 16 डीसीसीबी को 1639.71 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना शामिल था।
उत्तर प्रदेश सरकार ने एमओयू में उल्लिखित, रु. 1639.71 करोड़ की राशि के अतिरिक्त 2014-15 से 2021-22 की अवधि में रु. 471.65 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि 16 डीसीसीबी को जारी की है। इस तरह कुल धनराशि रु. 2111.36 करोड़ हुई। इस संबंध में बैंकों की सूची एवं जारी धनराशि निम्नवत है:-

क्रम सं	जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का नाम	कुल धनराशि (रुपये करोड़ में)
1.	इलाहाबाद	152.05
2.	आजमगढ़	124.51
3.	बहराइच	94.84
4.	बलिया	142.13
5.	बस्ती	128.33
6.	देवरिया	251.25
7.	फैजाबाद	29.17
8.	फतेहपुर	213.56
9.	गाजीपुर	69.69
10.	गोरखपुर	194.05
11.	हरदोई	95.65
12.	जौनपुर	181.65
13.	सिद्धार्थ नगर	63.64
14.	सीतापुर	131.81
15.	सुल्तानपुर	111.56
16.	वाराणसी	127.46
	कुल	2111.36